funds to conduct Lok Adalats in their respective States and if their funds are not adequate and when they approach, then the Central Committee is allocating a sum of Rs. 3,500/- per each Lok Adalat and in the circumstannces it can be treated as a continuous process.

Allowances paid to Employees of Central Schools at Moscow and Kathmandu

1301. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the details of different allowances, facilities, perks, etc. which are admissible to the different category of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan posted at Moscow and Kathmandu; and

(b) whether these are being revised shortly?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Allowances and facilities are generally made available according to the Government of India instructions in force for such foreign postings.

Authority Having powers to grant admission to Central Schools

1302. SHRIMATI KAILASHPATI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) which Authority/Officer of Kendriya Vidyalaya Sangathan are empowered to grant admission to different classes of the Kendriya Vidyalayas of the country to students of different categories;

(b) if so, the details of the decision alongwith the date thereof, conferring such powers;

(c) whether Members of Parliament have been given any 'quota' for admission in Kendriya Vidyalayas; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) The Principal is authorised to grant admission to a Kendriya Vidyalaya as per guidelines approved by the Board of Governors. Relaxation of the guidelines is considered by the Commisioner/Chairman in exceptional and deserving cases. The admission rules are laid down in article Nos. 87—94 of the chapter of X of the Education Code for Kendriya Vidyalayas.

(c) and (d) The children and dependent grand children of Member of Parliaments can get admission in a Kendriya Vidyalaya over and above the admissible class limits.

Payment of D.A. to Central Government Employees

1303. SHRI KAPIL VERMA:
SHRI RAMSINH RATHWA:
SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the 12 monthly average of the cost of living index as on the 30th June, 1991 on the basis of which additional dearness allowance became due to the Central Government employees w.e.f. 1st July, 1991; and

(b) what percentage of dearness alowance has become due at various levels w.e.f. the 1st July, 1991; and

(c) by when a decision to sanction additional dearness allowance to the employees is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) and (b) The 12 monthly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (General) (Base 1960—100) for the period ending 30th June, 1991 is likely to become available in the month of August. The percentage of Additional Instalment of Dearness Allowance

due from 1st July, 1991 would be calculated thereafter.

(c) Under the existing orders, the instalment of Dearness Allowance due from 1st July is payable with the salary of September.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया इत्यादि द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण का वितरण

1304. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन कृषकों, कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों, बेरोजगार छात्रों और निम्न वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको 1988 से लेकर आज तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं और इससे सम्बद्ध बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं ;

(ख) इस संबंध में प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या कितनी है कितने आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा कितने आवेदन विचाराधीन हैं तथा इनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आवेदन प्राप्त करने के पश्चात ऋण देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और कुछ दलालो ने आवेदकों से कमीशन भी लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कर्जदारो को दलालों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली उन किसानों, कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, बेरोजगार छात्रों और निम्न वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित श्रेणी-वार सूचना नहीं रखती जिन्हें किसी राज्य विशेष में बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं । यह प्रणाली प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या नामंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित राज्य-वार सूचना भी नहीं रखती है । अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों से गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के कमजोर वर्गों को कुल बकाया राशि की सूचना भेजने के लिए कहा जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का अग्रिम प्रदान करने के लिए सभी बैंकों को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटाया जाना चाहिए । बैंक शाखाओं को ऋण आवेदन पत्र या तो सीधे ही आवेदकों से प्राप्त होते हैं या राज्य के प्रायोजक एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं और तदनुसार उन्हें मंजूर किया जाता है । ऋणों के संवितरण में देरी या किसी बिचौलिए द्वारा ऋण-कर्ताओं को परेशान किए जाने से संबंधित बैंकों में प्राप्त शिकायतों को उपचारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा जांच की जाती है ।

Posts of P.G.T. in Central School, Moscow

1305. **SHRI ISH DUTT YADAV:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kendriya Vidyalaya, Moscow had been started in 1987 and posts of PGTs in Science and humanities had been sanctioned therefor;

(b) if so, whether it is also a fact that the post of PGT (History) has remained unfilled for the last four years and if so; and

(c) what steps have been taken or are contemplated to fill the vacancy?